माननीय न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया के समक्ष

आदर्श नाट्य संस्था अपने अध्यक्ष के माध्यम से - याचिकाकर्ता
बनाम
अशोक मेहता और अन्य- प्रतिवादी
2020 की सीआर संख्या 2492 नवम्बर 27/2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 227-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1907-O.7 RI। 11—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973—धारा 101, 156—विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963—धारा 41 (ज)—आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन सिविल न्यायालय द्वारा सीपीसी की अनुमति—आदेश को बरकरार रखा गया—ऐसे आवेदन पर विचार करते समय, केवल वाद पर विचार किया जाना चाहिए और वह भी समग्र रूप से—प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अंतरण या संपत्ति को चुनौती—नगरपालिका समिति, 1973 अधिनियम के तहत किसी भी नोटिस या कार्यवाही के लिए नहीं - सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं - आयोजित किया गया, सिविल कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आम जनता का मूल्यवान हित शामिल था और संपत्ति को कैसे स्थानांतरित किया जा रहा था और नगरपालिका समिति द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था।

यह माना जाता है कि आक्षेपित आदेश में दिए गए कारण अच्छी तरह से उचित हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट उक्त प्रावधानों के तहत एक आवेदन से निपटने के दौरान सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केवल वाद को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना है। इसे पूरे सार्थक तरीके से पढ़ा जाना चाहिए और वाद के साथ दायर दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (संक्षेप में '1973 अधिनियम') के तहत मूल्यांकन प्रविष्टि को चुनौती दी जा रही थी, जो कि कन्वेयंस डीड के अलावा उठाई गई चुनौतियों में से एक थी, जिसे प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में दिया गया था और क्या इसे शून्य और शून्य घोषित किया जाना था। इसी तरह विवादित प्रविष्टि और हस्तांतरण विलेख के ज्ञान की तारीख की दलील नहीं दी गई थी और इसलिए, यह सबूत का विषय था कि क्या मुकदमा सीमा के भीतर था। इस प्रकार यह माना गया कि वाद को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल एक पूरे के रूप में और राहत को अलग नहीं किया जा सकता है और आवेदन की अनुमति देने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

(पैरा 2)

आगे कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा 29.09.2020 को आवेदन दायर किया गया था, जिसमें 1973 के अधिनियम के प्रावधानों के कारण और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 (एच) के तहत क्षेत्राधिकार के वरिष्ठ वकील बार द्वारा तर्क दिया गया था।

(पैरा 14)

आगे कहा गया कि वादी द्वारा इसका विरोध किया गया था कि मुकदमा संपत्ति के अधिकार के संबंध में था और विवाद नागरिक प्रकृति का था। मर्यादा की शुरुआत ज्ञान की तारीख से हुई थी और वादी को नगर समिति द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने के बाद पता चलने पर मुकदमा दायर किया था। प्रतिवादी/वादी के पास वर्तमान वाद के अलावा कोई उपाय उपलब्ध नहीं था और इसलिए, वाद की अस्वीकृति के लिए याचिका ली गई थी।

(पैरा 15)

आगे कहा गया, कि इस प्रकार, उपरोक्त दलीलों से और ऊपर चर्चा किए गए कानून के अनुसार, यदि वाद को समग्र रूप से लिया जाना है, तो चुनौती प्रतिवादी नंबर 1-नगरपालिका समिति के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण है, जो विवादित भूमि पर निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार मुद्दा यह होगा कि क्या प्रतिवादी नंबर 3 को प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में जमीन हस्तांतरित करने का अधिकार है और नगरपालिका के रिकॉर्ड में इस तरह का आकलन किस आधार पर किया गया था। राजकोषीय उद्देश्यों के लिए 1973 अधिनियम के तहत जारी किए गए किसी नोटिस या कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई है, जिसके खिलाफ धारा 156 के प्रावधानों के अनुसार एक रोक है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में एक वैधानिक रोक है।

(पैरा 16)

आगे कहा गया, कि सिविल कोर्ट इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वाद को खारिज करने में अच्छी तरह से न्यायसंगत था कि आम जनता का मूल्यवान हित शामिल था और संपत्ति को कैसे स्थानांतरित किया जा रहा था और नगरपालिका

समिति द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार, यह साक्ष्य का मामला है और यह ऐसा मामला नहीं है जहां मुकदमा वर्जित है और वाद खारिज करने योग्य नहीं है, जैसा कि वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया है। यह आदेश 7 नियम 11 सीपीसी और क्षेत्र को धारण करने वाले कानून के मापदंडों के भीतर नहीं आता है।

(पैरा 17)

आगे कहा गया है कि परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की राय है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया है।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ता के वकील अक्षय कुमार जिंदल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वीके जिंदल।
आर.पी. डांगी, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील।

माननीय न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया

1) याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 3 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में विद्वान अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मेहम द्वारा पारित दिनांक 16.10.2020 (अनुलग्नक पी -4) के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
2) आक्षेपित आदेश में दिए गए कारण अच्छी तरह से उचित हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट उक्त प्रावधानों के तहत एक आवेदन से निपटने के दौरान सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केवल वाद को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना है। इसे पूरे सार्थक तरीके से पढ़ा जाना चाहिए और वाद के साथ दायर दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (संक्षेप में '1973 अधिनियम') के तहत मूल्यांकन प्रविष्टि को चुनौती दी जा रही थी, जो कि कन्वेयंस डीड के अलावा उठाई गई चुनौतियों में से एक थी, जिसे प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में दिया गया था और क्या इसे शून्य और शून्य घोषित किया जाना था। इसी तरह विवादित प्रविष्टि और हस्तांतरण विलेख के ज्ञान की तारीख की दलील नहीं दी गई थी और इसलिए, यह सबूत का विषय था कि क्या मुकदमा सीमा के भीतर था। इस प्रकार यह माना गया कि वाद को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल एक पूरे के रूप में और राहत को अलग नहीं किया जा सकता है और आवेदन की अनुमति देने के लिए उत्तरदायी नहीं था।
3) याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि संपत्ति का कब्जा अटल सामुदायिक केंद्र के निर्माण के उद्देश्य से नगर समिति, महम को सौंप दिया गया था और प्रतिवादी नंबर 1 सूट संपत्ति के कब्जे में था। वादी और प्रतिवादी नंबर 2 और 4 को इससे कोई लेना-देना नहीं था और यह बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था। एक बार रजिस्टर में मूल्यांकन किए जाने के बाद, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के खंड (डी) के मद्देनजर 1973 अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे चुनौती देने पर रोक लगा दी गई थी। 1973 अधिनियम की धारा 101 और 156 पर भरोसा किया गया था, जो निम्नानुसार है: -

> "**101. कराधान इस अधिनियम के तहत छोड़कर पूछताछ नहीं की जानी चाहिए**-
> (1) किसी भी मूल्यांकन या मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी, न ही किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन या कर लगाने के दायित्व पर किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम में प्रदान की गई तुलना में पूछताछ की जाएगी।
> (2) किसी भी कर की कोई वापसी इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा किसी भी व्यक्ति द्वारा दावा योग्य नहीं होगी।
>
> **156. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित-**
> तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी सिविल न्यायालय को किसी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाहियों में या धारा 154 या धारा 155 में निर्दिष्ट प्रतिकर या रकम या संविभाजन या उसके संदाय या उससे संबंधित किसी मामले में ग्रहण करने या निर्णय देने की अधिकारिता नहीं होगी।

4) तदनुसार, यह तर्क दिया गया था कि वादी के पास 1973 अधिनियम की धारा 99 के तहत अपील का एक वैकल्पिक प्रभावोत्पादक उपाय था और राज्य सरकार के समक्ष आगे अपील प्रदान की गई थी। धारा 11 के

अनुसार नोटिस के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर अपील दायर की जानी थी और वादी वर्ष 2012-2013 में किए गए मूल्यांकन से व्यथित था। मुकदमा 8 साल बाद वर्ष 2020 में दायर किया गया था। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 (एच) पर भरोसा किया गया था कि इस तरह से निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है और नगरपालिका समिति द्वारा प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि वादी का मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था।

5) दूसरी ओर प्रतिवादी-वादी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि सीमा का प्रश्न कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न था और विवाद संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि 1973 अधिनियम के प्रावधान एक प्रभावी उपाय प्रदान करेंगे। यह मुकदमा सीपीसी की धारा 91 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए दायर किया गया था। आदेश 7 नियम 11 (डी) सीपीसी के प्रावधान केवल यह प्रदान करते हैं कि जहां वाद में बयान से वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है, तो वाद खारिज कर दिया जाएगा।

6) राजेश ग्रोवर बनाम श्रीमती रीता खुराना के मामले में यह माना गया था कि वाद की अस्वीकृति एक बहुत ही गंभीर परिणाम था और न्यायालय को एक आवेदन से निपटने के दौरान दहलीज पर एक वाद को खारिज करने में चौकस रहना चाहिए, जिसके तहत वाद की अस्वीकृति के लिए प्रार्थना की गई है। मुद्दा यह था कि कार्रवाई का कोई नया कारण नहीं था, क्योंकि पहले के एक मुकदमे को वापस ले लिया गया था। परिणामस्वरूप, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वाद में ऐसी कोई दलील नहीं थी और न ही कोई मुद्दा तैयार किया गया था और मुकदमे की दलील को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, उचित स्तर पर फैसला किया जाएगा। इस प्रकार, उक्त आदेश को बरकरार रखा गया था।

7) पी.वी. गुरु राज रेड्डी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीपीए लक्ष्मी नारायण रेड्डी और अन्य बनाम पी. नीराधा रेड्डी और अन्य के मामले में कहा है कि वाद में कथनों को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मुकदमा किसी कानून के तहत वर्जित है। लिखित बयान या वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन में प्रतिवादी का रुख पूरी तरह से सारहीन था। परिणामस्वरूप, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन, जिसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, को वादी के कहने पर अलग कर दिया गया था। यह भी माना गया कि यह न्यायालय में प्रदत्त एक कठोर शक्ति है और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्तें, इसलिए, कठोर हैं और केवल वाद को ध्यान में रखा जाना है। संबंधित पैरा निम्नानुसार पढ़ा गया है: -

> "5. सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत वाद की अस्वीकृति एक कठोर शक्ति है जो अदालत में दहलीज पर एक नागरिक कार्रवाई को समाप्त करने के लिए प्रदान की गई है। आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्तें, इसलिए, कठोर हैं और न्यायालय द्वारा लगातार ऐसा माना गया है। यह वाद में कथन है जिसे यह पता लगाने के लिए पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि क्या यह कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है या क्या मुकदमा किसी कानून के तहत वर्जित है। आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति के प्रयोग के चरण में, लिखित बयान में या वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन में प्रतिवादियों का रुख पूरी तरह से सारहीन है। यह केवल तभी होता है जब वाद में कथन पूर्व दृष्टया कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करते हैं या उसके पढ़ने पर वाद किसी भी कानून के तहत वर्जित प्रतीत होता है, वाद को खारिज किया जा सकता है। अन्य सभी स्थितियों में, दावों को मुकदमे के दौरान स्थगित करना होगा।
>
> 6. वर्तमान मामले में, वाद को समग्र रूप से पढ़ना और इस आधार पर कार्यवाही करना कि उसमें किए गए कथन सही हैं, जो कि न्यायालय को करने की आवश्यकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त दलील से यह पता चलता है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत वर्जित है। कार्रवाई के कारण को जन्म देने वाले आवश्यक तथ्यों के ज्ञान के संबंध में वादी के दावे को सही माना जाना चाहिए। आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार के चरण में लिखित बयान में प्रतिवादियों का रुख पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा।"

8) इसी तरह, छोटाबेन और अन्य बनाम किरीटभाई जलकृष्णभाई ठक्कर और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि यदि कोई विचारणीय मुद्दा उठता है, तो वाद खारिज करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए अपील की अनुमति दी गई जिसने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन की अनुमति दी थी। उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वाद की इस प्रकार जांच की जानी है।

9) प्रतिवादी-वादी द्वारा मुकदमा दायर किया गया था कि वार्ड नंबर 10, महम (न्यू वार्ड नंबर 11) में एक गीता भवन मंदिर था, जिसकी देखभाल प्रतिवादी नंबर 4-पंजाबी धर्मशाला और गीता भवन मंदिर प्रबंधक समिति, महम द्वारा अपने कार्यवाहक अध्यक्ष के माध्यम से की जा रही थी। मंदिर के सामने भगवान शिव की एक मूर्ति, शिवालय, बैठक और अन्य इनडोर कार्यों के लिए हॉल मौजूद था। दुकान भूतल और एक सीढ़ी के ऊपर थी और पहली मंजिल पर कमरा था और पृष्ठभूमि में रामलीला के प्रदर्शन के लिए एक मंच और हवन, भंडारे और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए खुला आंगन था। नगरपालिका समिति ने गीता भवन मंदिर के रूप में निर्धारण वर्ष 1993-1994, 1999-2000 और 2001-2002 के लिए मूल्यांकन रजिस्टर में संपत्ति संख्या 5300 और 5300/1 के रूप में संपत्ति के लिए दो अलग-अलग नंबर यानी आगे का हिस्सा और पिछला हिस्सा निर्धारित किया था। संपत्ति संख्या 5300/1 को गीता भवन पंचायती के रूप में दिखाया गया था, और दोनों नंबरों की देखभाल प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा की गई थी। पिछले हिस्से का उपयोग गांव महम के निवासियों द्वारा वर्ष 1987 से धार्मिक उद्देश्य जैसे रामलीला आदि के लिए किया गया था और इस तरह की अनुमति ली जा रही थी। गांव के निवासी मंदिर को दान कर रहे थे और उन्होंने भवन और भगवान शिव की बड़ी मूर्ति का निर्माण करवाया था। क्षेत्र के लोग मंदिर और उसकी संपत्तियों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे।

10) विभिन्न रामलीला समितियों द्वारा रामलीला करने के लिए एक स्थायी रामलीला मंच का निर्माण किया गया था और प्रतिवादी नंबर 3 उनमें से एक था जो मंदिर के पिछले हिस्से में रामलीला करता था। मंदिर का दौरा करने पर, वादी ने रामलीला मंच को जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाया और गीता भवन मंदिर को वित्तीय मदद की पेशकश की गई, जब यह पता चला कि प्रतिवादी नंबर 1 के साथ मिलकर प्रतिवादी नंबर 3 ने उस क्षेत्र के लिए अवैध रूप से मूल्यांकन रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया था जहां रामलीला, भंडारे और अन्य धार्मिक कार्य किए जाते थे। प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में अवैध रूप से जमीन जारी की थी, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 3 का जमीन पर कोई अधिकार, शीर्षक और हित नहीं था। वर्ष 2012-2013 के मूल्यांकन रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि मंदिर के पिछले हिस्से को भवन उपयोग के शीर्ष के तहत धार्मिक के रूप में दिखाया गया था और श्रेणी के प्रमुख को मंदिर के रूप में दिखाया गया था। गीता भवन मंदिर के पिछले हिस्से के आसपास के विभिन्न लोगों के सेल डीड में गीता भवन मंदिर का उल्लेख था, न कि प्रतिवादी नंबर 3 का।

11) हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा गीता भवन में पंजाबी धर्मशाला के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये के अनुदान का उल्लेख किया गया। जिला कलेक्टर, रोहतक द्वारा दी गई अनुमति से यह भी पता चलेगा कि पंजाबी धर्मशाला का निर्माण उसी स्थान पर किया गया था जो अब सूट संपत्ति है और उक्त पत्र में इसे गीता भवन के रूप में लिखा गया था। प्रतिवादी संख्या 3, नगरपालिका समिति द्वारा 30.08.2011 को गीता भवन मंदिर के पश्चिम में पंजाबी धर्मशाला के निर्माण की जगह दिखाते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। यह आगे कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 और 3 ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रतिवादी नंबर 1-नगरपालिका समिति के पक्ष में सूट की जमीन जारी की थी, जिसे भी चुनौती दी गई थी। इस प्रकार कार्रवाई का कारण इस आधार पर था कि अटल सेवा केंद्र के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, जहां उक्त धार्मिक कार्य आयोजित किए गए थे और बिना शीर्षक के भूमि को बदलने की योग्यता पर आपत्ति की गई थी, जिसका मूल्य करोड़ों में था। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 4 अधिकृत व्यक्ति प्रतिवादी नंबर 2 के हितों की रक्षा करने में विफल रहा था। इस प्रकार, यह माना गया कि संपत्ति की प्रकृति को बदलने से बड़े पैमाने पर जनता की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुईं और मूल्यांकन रजिस्टर में सुधार की भी मांग की गई। कार्रवाई का कारण एक सप्ताह पहले उत्पन्न हुआ था जब सूट संपत्ति की एक दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के कारण, वे सफल नहीं हो सके।

12) प्रतिवादी क्रमांक 1/एमसी द्वारा दायर लिखित बयान दर्ज किया गया कि यह अटल सामुदायिक केंद्र का निर्माण कर रहा था और वादी ने लोक कल्याणकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रतिवादी क्रमांक 2 व 4 के साथ मिलीभगत से वाद दायर किया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि दो अलग-अलग संपत्तियां थीं और वादी और प्रतिवादी नंबर 2 को संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं था। एक अन्य मुकदमा पंजाबी धर्मशाला बनाम म्यूनिसिपल कमेटी, महम के रूप में भी लंबित था, जिसे प्रतिवादी नंबर 2 और 4 द्वारा धर्मपाल मेहता के माध्यम से दायर किया गया था, जो वादी के भाई (वादी के असली चाचा का बेटा) था। स्थगन आवेदन 18.09.2019 को खारिज कर दिया गया था और इसलिए वादी द्वारा दायर मुकदमा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था।

13) दलील दी गई कि रामलीला और रासलीला बजाने के लिए मंच प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा बनाया गया था और किसी अन्य व्यक्ति को इससे कोई सरोकार नहीं था। वादी, प्रतिवादी नंबर 2 और 4 न तो मालिक थे और न ही सूट संपत्ति के कब्जे में थे, जिसे आईडी नंबर 45 सी 141 यू 16 आवंटित किया गया था। इसका स्वामित्व

प्रतिवादी नंबर 3 के पास था, जिसने अटल सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को सौंप दिया था और परिणामस्वरूप मुकदमा लड़ा गया था।

14) प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा 29.09.2020 को आवेदन दायर किया गया था, जैसा कि 1973 के अधिनियम में प्रावधानों के कारण और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 (एच) के तहत क्षेत्राधिकार के वरिष्ठ वकील बार द्वारा तर्क दिया गया था।

15) वादी द्वारा इसका विरोध किया गया था कि मुकदमा संपत्ति के अधिकार के संबंध में था और विवाद नागरिक प्रकृति का था। मर्यादा की शुरुआत ज्ञान की तारीख से हुई थी और वादी को नगर समिति द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने के बाद पता चलने पर मुकदमा दायर किया था। प्रतिवादी/वादी के पास वर्तमान वाद के अलावा कोई उपाय उपलब्ध नहीं था और इसलिए, वाद की अस्वीकृति के लिए याचिका ली गई थी।

16) इस प्रकार, उपरोक्त दलीलों से और ऊपर चर्चा किए गए कानून के अनुसार, यदि वाद को समग्र रूप से लिया जाना है, तो चुनौती प्रतिवादी नंबर 1-नगरपालिका समिति के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण है, जो विवादित भूमि पर निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार मुद्दा यह होगा कि क्या प्रतिवादी नंबर 3 को प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में जमीन हस्तांतरित करने का अधिकार है और नगरपालिका के रिकॉर्ड में इस तरह का आकलन किस आधार पर किया गया था। राजकोषीय उद्देश्यों के लिए 1973 अधिनियम के तहत जारी किए गए किसी नोटिस या कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई है, जिसके खिलाफ धारा 156 के प्रावधानों के अनुसार एक रोक है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में एक वैधानिक रोक है।

17) सिविल कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वाद को खारिज करने में अच्छी तरह से उचित था कि आम जनता का मूल्यवान हित शामिल था और संपत्ति को कैसे स्थानांतरित किया जा रहा था और नगरपालिका समिति द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार, यह साक्ष्य का मामला है और यह ऐसा मामला नहीं है जहां मुकदमा वर्जित है और वाद खारिज करने योग्य नहीं है, जैसा कि वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया है। यह आदेश 7 नियम 11 सीपीसी और क्षेत्र को धारण करने वाले कानून के मापदंडों के भीतर नहीं आता है।

18) नतीजतन, इस न्यायालय की राय है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी